भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 187

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 6 दिसम्‍बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**तालचेर उर्वरक संयंत्र का पुनरुत्‍थान**

187. श्री नंद कुमार साय:

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या हाल ही में औद्योगिक और वित्‍तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने बोर्ड से भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के पंजीकरण को रद्द कर दिया है; यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है:

(ख) क्‍या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), राष्‍ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड (आरसीएफ) और गेल (आई) ओडिशा की तालचेर इकाई को पुन:चालू करने पर सहमत हो गए हैं; यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) इन कपनियों द्वारा इसे पुन:चालू करने के लिए तैयार की गई योजना का ब्‍यौरा क्‍या है और इस पर कितना खर्च आने की संभावना है: और

(घ) इससे रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क):** जी हां। औद्योगिक और वित्‍तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) ने दिनांक 27.06.2013 को आयोजित अपनी बैठक में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(एफसीआईएल) को बीआईएफआर के दायरे से बाहर कर दिया था।

**(ख) और (ग):** जी हां। एफसीआईएल सहित कोल इंडिया लिमिटेड(सीआईएल), राष्‍ट्रीय केमिकल्‍स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड(आरसीएफ), गेल(इंडिया) लिमिटेड ने उडी़सा में तलचर इकाई, जिसे वर्ष 2000 में बंद कर दिया गया था, का पुनरुद्धार करने पर सह‍मति दी है। एफसीआईएल, सीआईएल, आरसीएफ और गेल ने उड़ीसा में एफसीआईएल की तलचर इकाई का पुनरुद्धार करने के लिए 5 सितम्‍बर, 2013 को एक समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए हैं। परियोजना प्रवर्तक आरसीएफ, गेल, सीआईएल (और एफसीआईएल) स्‍वयं मिलकर दो संयुक्‍त उद्यम(जेवी) कंपनियां अर्थात् जेवी-I और जेवी-2 बनाएंगी। जेवी-I मुख्‍यत: पूर्व-अर्हकता प्राप्‍त प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता के बाद

-2-

एकमुश्‍त टर्नकी(एलएसटीके) आधार पर अपस्‍ट्रीम कोयला गैसीकरण और गैस शुद्धिकरण खण्‍ड की स्‍थापना के लिए जिम्‍मेदार होगी। गेल की जेवी-I में प्रमुख हिस्‍सेदारी होगी और यह कार्यान्‍वयन हेतु नोडल एजेंसी होगी। पीएसयू की संयुक्‍त हिस्‍सेदारी हर समय 51% से अधिक बनी रहेगी। जेवी-2 अमोनिया-यूरिया, नाइट्रिक एसिड-अमोनियम नाइट्रेट संयंत्रों की स्‍थापना करने के लिए जिम्‍मेदार होगी। प्रमुख हिस्‍सेदारी आरसीएफ और सीआईएल के पास होगी। आरसीएफ डाउनस्‍ट्रीम संयंत्रों और ऑफ साइटों और उपयोगिताओं के कार्यान्‍वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। परियोजना-पूर्व कार्यकलाप शुरु कर दिए गए हैं, ताकि विस्‍तृत व्‍यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) तैयार की जा सके। डीएफआर तैयार करने के लिए कार्यकलापों से संबंधित संपूर्ण लागत को गेल, आरसीएफ और सीआईएल द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। कुल परियोजना लागत 9000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

**(घ):** परामर्शदाता मैसर्स प्रोजेक्‍ट्स एण्‍ड डेवलेपमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्‍तुत प्रौद्यो-आर्थिक व्‍यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार पुनरुद्धार से साइट पर लगभग 760 नौकरियों के अवसर पैदा होने की संभावना है।

\*\*\*\*\*